

Samyak

An Institute For Civil Services

RAS - 23 MAINS TEST SERIES

सिद्धि - 09/A8

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 200

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
Indian Political System

Paper - III (Unit-I)

Name :		MARKS	
Enroll. No.:	Part	Attempted Questions	Marks Obtained
Date of Birth :	Part - A		32
Medium : हिंदी	Part - B		44
E-mail :	Part - C		24.5
Exam Date : 17 Dec. 2023	Total		100.5/200
Inviligator's Signature : Anand Keshh			
ECN:	RCN: 007	Hindi: 0/20	English: 0/20

अनुदेश (Instructions)

- परीक्षा शुरू होने से पहले पुस्तिका को जाँच लें।
Please check the booklet before commencement of the exam.
- दिये गये रिक्त स्थान में निर्देशित शब्द सीमा में उत्तर दें।
Write the answers according to the prescribed word limit, in the space given.
- अंक योजना प्रत्येक खंड के प्रारम्भ में दी गई है।
The marking scheme is given at the start of every section.
- परीक्षा के पश्चात् उत्तर पुस्तिका हॉल अधीक्षक को सौंप दें।
Return the answer booklet to the hall superintendent after completing the paper.

SAMYAK, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur, 9875170111
Test Series Helpline & Whatsapp - 9414988860, Email Id - samyakttestseries@gmail.com

	REVIEW PARAMETERS	SCALE			
		Good	Above Average	Average	Below Average
1.	DOES THE ANSWER ADDRESS THE DEMAND OF THE QUESTION?				
a.	Answer Relevancy		✓		
b.	Answer Enrichment points like use of: · Key Terms/ Subject Vocabulary. Use of Commission/ report/ government publication/ judgements, etc. Association with the Current Affairs and use of examples to explain the concept and idea		✓	✓	
2.	HOW WELL IS THE ANSWER PRESENTED?				
a.	Structure - Intro, Body, Conclusion			✓	
b.	Presentation – Using Subheadings/ points/ highlighting/ flowcharts/ diagrams/ maps				✓
c.	Language & Grammar		✓		
d.	Word limit		✓		

Detailed Comments/ Feedback / Suggestions for Improvement
विस्तृत टिप्पणियाँ/फीडबैक/सुधार के लिए सुझाव :-

1. हिंदी व अंग्रेजी व्याकरण का अभ्यास करने की आवश्यकता
2. विषय संबंधी आधारभूत शब्दावली को हरीय भाषा में याद
3. करें।
4. निर्धारित सीमा समय का ध्यान रखें।
5. उत्तर संक्षेप में विषयता उद्देश्य करें। फ्लो-चार्ट का
6. प्रयोग करें।
7. व्याख्यान करने हेतु जो आवश्यक हो संबंधित उद्धरण
8. अधिक तथ्य / किर्तय / रिपोर्ट / उद्धरण को भी प्रस्तुत करें
- 9.
- 10.
11. टु-टू पॉइंट लेखन का अभ्यास करें

Note : Answer the following questions in 15 words. Each question carries 2 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. राजनीतिक गत्यात्मकता से क्या तात्पर्य है?

What is meant by political dynamism?

राजनीति में मतदान व्यवहार, नवीन आवाजों व पौद्योगिकी की आविष्कार, जिससे दबाव समूह, राजनीतिक दलों के निर्णय क्षमता कमिज हो ऐसे कारक जो राजनीति का गतिशीलता उदात्त करने जाते हैं।
बाध, माध।

(Write above this line only)

2. भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के किन्हीं चार कारणों को लिखिए।

Write any four reasons for the rise of regional political parties in India.

संमुख कारण →

- ① क्षेत्रीय मुद्दे
- ② आवेगित प्रभाव
- ③ भाषाई - नृजातीय आधार - द्वासमगर्ण परिष्क
- ④ परंपरागत प्रभाव - जातिवाद, समाजवाद - 1970 में स्वतंत्र पार्टी का उदभव।

(Write above this line only)

3. स्वापक आतंकवाद को परिभाषित कीजिए।

Define narco-terrorism.

द्वैध रूप से प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी, संग्रहण, व्यापार करना स्वापक आतंकवाद है। जैसे - हेरोइन, चरस, कोकाइन का सीमापार हानिकारक द्वारा पहुंचाना। बेलजियम के N.D.P.S अधिनियम 1985।

(Write above this line only)

4. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले चार कारक लिखिए।
Write four factors affecting voting behaviour.

- ① सरकार की नीतियाँ, राजनीतिक दलों का घोषणापत्र।
- ② क्षेत्रीय मुद्दे - संरक्षक, सुरक्षा, जल, स्वास्थ्य।
- ③ जातीय प्राथम्यता → विभिन्न जाति पंचायतें का विचार।
- ④ दबाव समूह → सरकारी नीतियों की समीक्षा द्वारा।

(Write above this line only)

5. तदर्थ दल
Ad-hoc political party

कुछ तात्कालिक मुद्दों को लेकर जनधर्मसेतु को व्यक्त करने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ, जैसे - जम्मू-कश्मीर में उपकार संगठन। इनका प्रभाव सीमित व अस्थायी होता है।

(Write above this line only)

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलू लिखिए।
Write the aspects of freedom of expression.

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के रूप में लक्षित है। इसमें वाक्-अभिव्यक्ति, प्रेस की, विज्ञापन की, RTI से सूचना मांगने, जनवाद दाखल करने की स्वतंत्रता शामिल है।

(Write above this line only)

10. भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता क्यों है?
Why is free legal aid needed in India?

सामाजिक-आर्थिक जमाइकी के व्यापक पिछड़े जनधार, कानूनी साक्षरता की कमी के चलते लोककल्याणकारी राज्य के लक्ष्य प्राप्त हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता की जरूरत है। गलत दसमिद्धि से रोकना के लक्ष्य विधिक सेवा प्राधिकरण रक्षी दिशा में प्रयास है।

(Write above this line only)

11. वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार बताइए।
Explain the types of alternative dispute resolution.

एकीकृत न्यायिक प्रणाली पर दबाव को कम करने हेतु -
① राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (रादा)
② IARPSA एकर वितीय धोरणधी संबंधी मामलों के समाधान।
मुख्य मध्यस्थता

(Write above this line only)

12. सातवीं अनुसूची।
Seventh Schedule.

भारतीय संविधान के संघात्मक शक्तिविभाजन के रूप में शक्तियों के विभाजन विषयक विवरण - ① संघ सूची - 100 विषय, केन्द्र कानून बना सकते हैं। ② राज्य सूची - 61 विषय, राज्य कानून बना सकते हैं। ③ समवर्ती सूची - 52 विषय, केन्द्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ④ शक्ति विभाजन - केन्द्र राज्य का ध्यान रख

(Write above this line only)

13. मंत्रिमण्डलीय समितियाँ
Cabinet Committees

सर्वकार के प्रमुख मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने हेतु, वर्तमान में 8 मंत्रिमण्डलीय समितियाँ हैं।
इनमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। प्रकार - (1) द्विदिवसीय संसदीय (2) राजनीतिक नियुक्ति संबंधी (3) संसदीय मामलों की (4) हाथकान संबंधी (5) विशेष - इसके विषय संसदीय नदी संबंधी।

(Write above this line only)

14. भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
Under which Act and in which year was the Public Service Commission established for the first time in India?

सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 1923 में ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1926 में - फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना।
1 अक्टूबर

(Write above this line only)

15. दया याचिका की आवश्यकता को समझाइए।
Explain the need for mercy petition.

राष्ट्रपति द्वारा अगुवोड 72 के तहत मृत्युदण्ड की सजा प्राप्त अभियुक्त द्वारा सजा पर पुनर्विचार कर दामा करने का प्रार्थना पत्र।
व्यापकता
उपरोक्त
करें

(Write above this line only)

16. रिमोट वोटिंग के पक्ष में तर्क दीजिए।
Give arguments in favor of remote voting.

भारतीय निर्वाचन आयोग का नवाचार, हस्त के बिधानसभा चुनावों में प्रयोग - वृद्धजन व दिव्यांगों हेतु घरसे वोटिंग।

पक्ष ① मतदान प्रतिशत बढ़ना
② वृद्धों - दिव्यांगों के कल्याण की दिशा में काम
③ इन संवेदनशील वर्गों की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना।
④ इ मतदान का अधिकार से सरकार की सक्रियता सुनिश्चित।

17. सामाजिक लोकतंत्र क्या है?
What is social democracy?

समाज के सभी वर्गों (उच्च-पिछड़े, युवा-वृद्ध, महिलाएं) को एक लोकतंत्र की पद्धति में मतदान में हिस्सेदारी, रिकट बंटवारे में स्थान, मंत्रिमंडल में फर्मिष्ठ प्रतिनिधित्व।
दुर्जीवारी व्यवस्था में सामाजिक न्याय।
उदा. - नार्वे, स्वीडन

(Write above this line only)

18. अनुच्छेद 142 की आलोचना कीजिए।
Criticize Article 142.

शीर्षक अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के तहत विपक्षी पार्टी को वास्तव में न्याय देता है।
जैसे - काबूरी माइजिद के।
शक्तिशाली और प्रभावशाली विद्वानों का उत्तम धन।
आलोचना → गैर हकथारी को अधिकार के धारक नहीं।

(Write above this line only)

19. दलों में आन्तरिक लोकतंत्र को बढ़ाने के उपाय बताइए।

Tell the ways to increase internal democracy in parties.

- ① संस्यनात्मक बदलाव ^{कार्यवाही के कदम न हिए} (i) सभी वर्गों का पथसि प्रतिनिधित्व
- (ii) महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित - वीसू जनता दल की तर्ज पर
- ② आंगणिक फाधिकारियों के चयन में - वंशवाद-धनबल न चले।
- ③ आंतरिक कार्यवाही निष्क्रिय बल का प्रयोग हो।
- ④ उचित व सम्यक प्रणाली के लोगों को संगठन में जगाए।
- ⑤ समय-समय पर संगठन में चुनाव हो।

(Write above this line only)

20. इन्दिरा साहनी वाद (1992) के निर्णय के बिन्दुओं को लिखिए।

Write the points of the decision of Indira Sawhney case (1992).

लोकसेवाओं में आरक्षण विषयक वाद, प्रमुख बिंदु न

- ① सरकारी सेवाओं में आधिक्यतम आरक्षण पदों का 50% रहनी।
- ② पिछड़े वर्गों का आरक्षण संविकान सम्मत है।
- ③ आर्थिक आधार पर आरक्षण ठीक है।
- ④ अर्थ पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देकर शेष आरक्षण को सरकारी सेवाओं में वितरित करना है।

(Write above this line only)

21. पेसा अधिनियम की सीमायें लिखिये।

Write the limitations of PESA Act.

- 1996 में जनजातीय क्षेत्रों में PESA (पंचायतीराज क्षेत्र विस्तार अधिनियम) लागू हुआ। सीमाएं →
- ① पंचायतों को पथसि वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई।
 - ② सीमांकन → कुछ क्षेत्र जनजातीय होने के बावजूद शामिल नहीं।
 - ③ महिलाओं को प्रभावित होकर नहीं।
 - ④ कमोपज आदि के उचित मूल्य का संविकानिक प्रावधान नहीं।
 - ⑤ पिछड़े वर्गों के हेतु विशेषता का आरक्षण।

केंद्र में
राज्य
जानकारी
न
समाप्त

22. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
Aspirational Block Program

SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर संवर्धित। राजस्थान की कोटा पंचायत इसमें शामिल। कार्य (अभियान विषयों) पर कार्य ① सूक्ष्मतम विंडो तक पहुँच ② विद्येय की इतर करण।

(Write above this line only)

23. स्थानीय स्वशासन की लेखा परीक्षा का महत्व बताइए।
Explain the importance of audit of local self-government.

स्थानीय स्वशासन हेतु ग्रामसेवक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख लेखा अधिकारी। महत्व (अभियान विषयों) बना रहता है। ① कार्यों की जाँच व प्रगति समीक्षा ② वार्षिक निवेदन में सहभाग।

(Write above this line only)

24. नियम 184 एवं नियम 193 में अन्तर बताइए।
Explain the difference between Rule 184 and Rule 193.

संसदीय कार्यवाही के नियम 184 के नियम 193 में लोकसभा में चर्चा के दौरान अनुशासन बनाए रखने हेतु मूद्रा पर विचार समन्वय केवल विचार।

(Write above this line only)

25. भूले जाने का अधिकार
Right to be forgotten

दाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में शामिल किमी वाद, धारोप या अन्य तरह से पंच में जाने के बाद दोषी सिद्ध न होने की स्थिति में सोशल मीडिया आदि पर संबंधित कंटेंट को हटाए जाने से संबंधित हैं।

(Write above this line only)

Note : Answer the following questions in 50 words. Each question carries 5 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

1. दल-बदल विरोध कानून के क्रियान्वयन में विसंगतियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।
Give your suggestions to remove discrepancies in the implementation of the Anti-defection Law.

- परिचय सुझाव
- ① आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो।
 - ② दल-बदल संबंधी निर्णय हेतु स्पीकर के लिए समभावधि निर्दिष्ट हो। - किहीते होलोन वाद।
 - ③ दल बदलने वाले सदस्यों के पुनः चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति पीरियड हो।
 - ④ इसे रोकने हेतु स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन हो।
 - ⑤ दोषियों की सजा के अस्तित्व प्रावधान हो।
 - ⑥ संविधान संशोधन द्वारा कठोरता हेतु नियम बनाए जाएं।
 - ⑦ जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जन-जागरूकता।

(Write above this line only)

संक्षिप्त
परिचय
की
सुझाव
के

2. मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ स्पष्ट कीजिए।
 Explain the major challenges regarding the theory of basic structure.

शंखित परिच्छ (परिच्छेद)
 कृषावधि भारतीय वाद (1973) से उद्भूत मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान की अप्रतिम विशेषता है। इस संबंध में चुनौतियाँ → ① मूल ढांचे में क्या-क्या शामिल है इसका स्पष्ट निर्धारण नहीं। ② कुछ राज्यों की व्याख्या अस्पष्ट। ③ कई बार सरकार के साथ टकराव की स्थिति। ④ कार्यकारी सरकार पर एक तरह से *दंडाधीन शासन* के रूप में। ⑤ नित नवीन सिद्धांतों का उभरना।
मंत्रालय
मंत्रालय
मंत्रालय

पब्लिक का जगह में

(Write above this line only)

3. हेट स्पीच को परिभाषित कीजिये तथा इससे निपटने के सुझाव दीजिए।
 Define hate speech and give suggestions to deal with it.

परिभाषा
 यह अधिनियम 2000 के तहत व सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की व्याख्या के क्रम में - किसी व्यक्ति, वर्ग, भाषा, लिंग, नस्ल, संघर्ष के संदर्भ में गैर-मर्यादित *व्यक्त* हेट स्पीच है। ② *रोकने के उपाय* →
 ① कानूनी प्रावधान हो। ② स्पष्ट परिभाषा लग हो।
 ③ रोकने हेतु जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। ④ साइबर सुरक्षा - सोशल मीडिया संबंधी प्रावधान सख्त हो। ⑤ सामाजिक समरसता का माहौल हो।
 ⑥ संबंधित खुदियां तंत्र सजग रहे। ⑦ एकीकृत रेस्पॉन्सरी का गठन किया जाए।

परिच्छेद की संरचना के निर्धारण का सुझाव से अधिक स्पष्ट है

(Write above this line only)

4. जातिगत जनगणना क्या है तथा इसके पक्ष में तर्क दीजिए।
What is caste census and give arguments in favor of it.

लिखित - पिरायाम में
दली द्वारा मोग व बिहार में संपन्न जातिगत जनगणना में राज्य में निवासरत लोगों का जाति आधारित विवरण। हाल में कई राजनीतिक
पक्ष में तर्क 1) भारतीय समाज में अधिकांश वर्ग अश्वी श्री पिछड़े है, यतः उनकी पहचान करने हेतु
2) सामाजिक योजनाओं का लाभ लाभित समुदाय तक पहुंचाने हेतु
3) "जितनी आगीदारी- उतने संघर्षों पर एक" की व्यवस्था।
4) पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु 5) योजनाओं की प्रतिक्रिया
निष्पादन क्षमता में सुधार हेतु 6) गैरजकारी लाभ लेने वाली जातियों की हंशनी हेतु।

(Write above this line only)

5. भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान लिखिये।
Write the constitutional provision to promote cooperative federalism in India.

संघीय प्रणाली
सहकारी संघवाद → केन्द्र व अरक्षियों के मध्य सहयोग के प्रयास। इस हेतु संविधान में प्रावधान →
अनुच्छेद - 1 - भारत राज्यों का संघ है।
अनुच्छेद - 7 - शासियों का स्पष्ट विभाजन - संघकारी राज्यपाल की नियुक्ति - अनुच्छेद 152 उतहत।
अंतर्राष्ट्रीय परिषद - अनुच्छेद 243 उतहत आपकी समस्य हेतु
क्षेत्रीय परिषद - 1980 में गठित - उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, पूर्वोत्तर
GST परिषद → राज्यों की 2/3 वर श्रेय के साथ कर हिलेकी
अनुच्छेद 262 के तहत नदी नदी प्रियद हेतु निवहन तंत्र।
करवसूली, कर आदासगी अधिकार आदि।
मिहारास लोगों का ह्यपन रथ

उत्तर
रूपचर
मंत्रिपरिषद
उदाहरित
परिचय
परराष्ट्रक
के तथ
मुख्य
विंड
परिषद
वनाकर
उत्तर
कर

6. अंतर राज्यीय सीमा विवादों के कारण लिखिये।
Write the reasons for inter-state border disputes.

- कुछ ऐतिहासिक, भौगोलिक, नृजातीय दावों के कारण उत्पन्न विवाद। जैसे- महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल - ओडिशा, राजस्थान - गुजरात आदि।
- कारण → 1) ऐतिहासिक कारण → इतिहास में कोई क्षेत्र किसी विभासत अधीन रहे होती उसे लेकर अनेक राज्यों
- 2) भौगोलिक → भू-स्थिति व इन्धन संसाधनों की लेकर दक्षिण भारत में भूमि-पुत्र की विवादों।
- 3) भाषाई कारण → विवाद का प्रमुख कारण - बोलचाल क्षेत्र पर कर्नाटक-महाराष्ट्र का दावा इन्हीं कारण है।
- 4) नृजातीयता → पूर्वतर में अलग राज्यों की मांग - मणिपुर में कुची, मैत्री संघर्ष।
- 5) सांस्कृतिक उभाव → सांस्कृतिक समानता वाले हिस्सों द्वारा।

करीब
अरब
उत्तर
हृदय
पर
ध्यान
है

7. संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हुए, इनसे जुड़ी चुनौतियाँ बताइए।
Define parliamentary privileges and explain the challenges associated with them.

संसदीय विशेषाधिकार - अनुच्छेद 105 (विधानसभा हेतु 194)
के तहत संसदीय गरिमा, संसदीय सातत्य स्थापित करने हेतु सदस्यों को - गिरफ्तारी, मुकदमेबाजी, सरन में शामिल करने हेतु प्राप्त विशेषाधिकार।

चुनौतियाँ → माननीय सदस्यों द्वारा उनका उल्लंघन।
→ इनकी भाड़ में संसदीय गरिमा अंग - कई बार सदन से निष्कासन।
→ हाल में मधुका मोदरा का निलंबन।
→ अल्पसंख्यक व अधिसंख्यक विधायकों का उल्लंघन।
→ लोकतंत्र की मूल आवश्यकता के विपरीत। → आपराधिक व अनैतिक गतिविधियाँ से बच जाना चाहिए।

8. भारत में दबाव समूह कार्यशैली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
Critically evaluate the working style of pressure groups in India.

दबाव समूह → लोगों का संगठन जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजनीति में संलग्न हुए बिना प्रभाव डालते हैं - जैसे - फिक्की ।

हालांकि कई मामलों में दबावस्वरूप लोकनीति को प्रभावित कर जनहितैषी निर्णय हेतु कार्यरत रहते हैं लेकिन कई बार इस सीमा को पार कर जाते हैं →

- ① सरकार पर अनावश्यक दबाव
- ② संसाधनों के उचित आकलन के बिना अपने पक्ष में करने हेतु प्रयास
- ③ सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप
- ④ राजनीति विरोधक द्वारा नकारात्मक प्रभावित
- ⑤ जनता को बरगलाना
- ⑥ कर्तृपार शिथिल गतिविधियाँ - भारत सरकार के कई लाभार्थी रद्द किए

9. मूल अधिकार- मर्यादाएँ हैं। स्पष्ट कीजिए।
Fundamental rights- are limitations. Explain.

भारत संविधान के भाग-3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार नागरिकों के विकास हेतु बलभूत बिंदु हैं। सर्वोच्च

→ ~~अध्यात्म ने व्याख्या में कहा कि राज्य विधि के द्वारा~~ ~~विधायक संसद की शक्तों को मर्यादित करता है~~ ~~इसमें बदलाव कर सकता है। अपनी प्रकृति में ये अल्लंघनीय~~ ~~नहीं हैं।~~ इसी दिशा में पूर्व में संपत्ति के अधिकार - 19(F) व 31 को इस श्रेणी से हटाना पड़ा। साथ ही समग्र संपत्ति शक्ति सहित कई प्रावधान जोड़ भी गए। कोई भी व्यक्ति इस अधिकार पर वाद दायर नहीं कर सकता कि इस निर्णय से मूल अधिकार सीमित हो रहे हैं, क्योंकि वह मूल संसदात्मक अल्लंघन न करे।

आलोचनात्मक
प्रभावित
व्यक्ति
संसाधन
प्रत्यक्ष
सर तथा
सकारात्मक
निर्णय

कार्यक्रम
प्रकार
माँगा
अनुक्रम
आवश्यक
जागरूक
अभाव
ह

10. चुनाव में प्रौद्योगिकी का महत्त्व एवं चुनौतियाँ बताइए।

Explain the importance and challenges of technology in elections.

महत्त्व
परिचय
विषय
उद्देश्य
महत्त्व

महत्त्व → व्यक्तित्व व पारदर्शिता हेतु - EVM व वीपैट
 → ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम जुड़वाना। प्रत्या में मदद।
 → नियंत्रण हेतु C-विजिल एप से निगरानी।
 → जागरूकता हेतु स्वयं कार्यक्रम। (ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी धोखाधड़ी रोकना)
 → प्रशासन की CCC (कमांड - कंट्रोल - को-ऑर्डिनेशन) में सक्षमता।
 → व्यक्तिगत मतगणना, पारदर्शिता - जवाबदेयता (रिकॉर्डिंग लाइव टेलीकास्ट)

चुनौतियाँ → सफ़र छूट - हैकिंग की आशंका
 → कहीं-कहीं नेटवर्क की समस्या, तकनीकी खामी।
 → गलत अभिमत व दुरुपयोग → मतदान खर्चों में ऑनलाइन
विनाशपूर्ण परिणाम नहीं। → दुरुपचार - आचार संहिता का उल्लंघन

(Write above this line only)

11. राजनीतिक जनान्किकी का अर्थ समझाते हुए हाल ही में संपन्न राजस्थान 16वीं विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिये-
 Explaining the meaning of political demography, throw light on the representation of women in the recently concluded Rajasthan 16th Assembly.

राजनीतिक जनान्किकी → जनसंख्या का वह समूह जो
मतदान करने, चुनाव जीतने व प्रत्याशी रूप में पंजीकृत
करने की दृष्टि से महत्त्व रखता है। इस बार मात्र 20 महिलाएं
विधायक बनीं जो पिता जनसंख्या
16वीं विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व व हाल में संपन्न
विधानसभा - चुनाव में - महिला मतदान पुरुषों की अपेक्षा
आधे से अधिक जो उनकी ससशस्त्रीकरण (शक्ति है)।
प्रतिभागी → पंजीकृत राजनीतिक दलों ने महिला प्रतिभागियों को
निर्वाचित महिलाएं कम मौका दिया।
जीत → इस बार मात्र 20 महिलाएं चुनाव जीतीं जो 10% हैं।
महिलाओं के लिए पिछली बार 28 (14%) से संख्या कम है।

(Write above this line only)

12. छोटे राज्यों की मांगों की उत्पत्ति बताते हुए, दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
Explaining the origin of the demands of small states, throw light on the need for a second State Reorganization Commission.

- ① छोटे राज्यों की मांगों की उत्पत्ति → राज्यों के कुछ क्षेत्रों का पिछड़ापन व संसाधनों पर इनका हक के अधिकार के रूप में।
- ② आकार में विशाल राज्यों के अस्थिर शासन की मांग के रूप में उत्तर-प्रदेश से 4 राज्यों (पूर्वप्रखण्ड) राजस्थान से मकरभूमि की मांग।
- ③ भाषाई आधार पर कर्नाटक व केरल के छोटे हिस्सों द्वारा गोरखालेण्ड की मांग।
- ④ जनजातीयता व सांस्कृतिक पहचान के रूप में उत्तरपूर्व की जनजातों की मांग। कुकी, मैलेई, गोरखालेण्ड के रूप में।
- ⑤ अलगाववादी व क्षेत्रीय संकुचित हितों के लिए - दक्षिण राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात के आंशिक हिस्सों से भीलखण्ड की मांग।

दूसरे पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता → क्षेत्रीय गतिरोधों को रोकने व जनता की मांगों पर उचित विचार-विमर्श की दिशा में आवश्यक है। संसाधनों का पर्याप्त वितरण हो उस रूप में सरकार को इस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. 'भारतीय राजनीति के स्वरूप नियमितीकरण में आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है' स्पष्ट करें-
Explain 'Economic elements play an important role in regularizing the form of Indian politics'.

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति व राजनीतिक स्थिरता आपस में सह-संबंध होती है। विगत 2 दशकों से आर्थिक प्रगति व वैश्विक संकटों - 2008 वैश्विक मंदी, कोविडकाल (2020-21) के बावजूद प्रगति के आर्थिक तत्व उत्पादन में कृषि-उद्योगों की भागीदारी, सरकारी सहायता - MSME, SHG आदि से पुनर्जागरण रूप से संतोषजनक स्थिति रही। वहीं कुछ देशों - पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में आर्थिक तत्वों की प्रतिफलता यहां की राजनीतिक उलझाव में स्पष्ट दिखी।

सरकार द्वारा आर्थिक प्रगति व जनता द्वारा उत्पन्न लाभ भारतीय राजनीति के नियमितीकरण में सहानुभूति है।

आर्थिक तत्वों की निर्धनता व कठिनाई

14. न्यायिक बहुमतवाद का तात्पर्य बताते हुए, इसकी आलोचनाएँ लिखें।
 Explaining the meaning of judicial majoritarianism and writing its criticisms.

अनुच्छेद 145 के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय हेतु संविधान पीठ गठित की जाती है। आम तौर पर 5-7 या 8 पीठ ही निर्णय देती है। बहुमतवाद 3 जब संविधानपीठ द्वारा उच्च न्यायालय की संविधान पीठ में 1, 2 जजों की बहुमत के अभाव, अल्पमत समझति से निर्णय लिया जाता है। जैसे 6-7 (केशवानो भारतीय मामला)।

आलोचनाएं → 02 जजों के मत को खारिज कर दिया जाता है जैसे - नोरकोई मामले में U.V. नागरला का मत खारिज निर्णय-तर्क-तथ्यों के आधार पर दिए जाते हैं, जबकि यह विरोधों की कमी होती है।

15. वर्तमान संदर्भ में नीति आयोग के समक्ष कौन-कौनसी चुनौतियां हैं?
 What are the challenges before NITI Aayog in the present context?

परिणाम → नीति आयोग भारत का प्रमुख थिंक टैंक व सहकारी संघर्ष का उपकरण है। इसके समक्ष चुनौतियां →

- 1) यह संवैधानिक या सांविधिक नियम नहीं है।
- 2) प्रतिस्पर्धा के चलते कई राज्यों इनके मानकों की पहचान नहीं करते → पारदर्शिता, अंगार जिला इकाओं/शिकायतों में शामिल नहीं।
- 3) वित्तीय शक्तियों का अभाव।
- 4) टीम इंडिया में सभी मुख्यमंत्रियों का भाग न लेना।
- 5) इसकी सिफारिशों का अभाव नहीं है।

16. प्रिवेंटिव डिटेन्शन का अर्थ स्पष्ट करते हुए, इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए।
Explaining the meaning of preventive detention, throw light on the issues related to it.

प्रिवेंटिव डिटेन्शन अर्थात् - निवारक निरोध एक
उपाय है जिसमें अपराध की आशंका के आधार पर
किसी को नजरबंद किया जा सकता है। ताकि - संभावित
अपराध से बचा जा सके। प्रमुख मुद्दे
PSA, 1980 के तहत फारूक अब्दुल्ला की हिरासत।
पूर्व में शेख अब्दुल्ला भी इसी के तहत उद्द। महबूबा मुश्ताक
समेत कई नेताओं को इनो केस के संबंध में नजरबंद
UAPA, PSA, स्वापक निरोध अधिनियम 1985 के तहत निवारक
नजरबंदी।
अनुच्छेद 20, 22 में अधिकतम उमर की बाधा हटाने के बारे
झारा निवारक अधिनियम 1985 का विरोध किया गया है।

प्रिवेंटिव
उद्द
(3)
स्वापक
के

[Faint handwritten text, mostly illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.]

Note : Answer the following questions in 100 words. Each question carries 10 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. सर्वोच्च न्यायालय में संरचनात्मक सुधारों पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की हालिया घोषणा के संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।

Structure Discuss the possible implications of Chief Justice D.Y. Chandrachud's recent announcement on structural reforms in the Supreme Court.

परिचय मुख्य बिंदु विवरण -
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के हालिया वक्तव्य \Rightarrow न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रभाव \Rightarrow मुख्य न्यायाधीश महोदय ने डिजिटल कमरों के अद्यतन के वक्तव्य में बताया कि इससे - मामलों का त्वरित निपटारा, \rightarrow सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में सहभागिता। \rightarrow अल्पकालीन - मामलों की दरम्यान में सहभागिता।

- लाइव स्ट्रीमिंग से विधिक जागरूकता बढ़ेगी। \rightarrow सत्रिय पत्रों की स्थापना

संरचनात्मक सुधार संबंधी \Rightarrow विशेष विशेष संबंधी स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना हो। \Rightarrow रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती हो \Rightarrow मामलों का स्थानीय आपा में दुरुदाई \Rightarrow हाइकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय के जजों के स्थानांतरण हेतु विरोध सुबिधा तंत्र (SFS) हो। \Rightarrow कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करने में क्लिंख न हो।

इस प्रकार न्यायिक इरी से बचने हेतु अ.प्रशासकीय वक्तव्य के गहरे मायने हैं।

कर्ट के सही व स्त्रीय जानकारी का अभाव है अध्यापक

12

Write above this line only

2. पिछले तीन दशकों में, पंचायतों में महिला आरक्षण की यात्रा परिवर्तनकारी रही है; निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
Over the last three decades, the journey of women's reservation in Panchayats has been transformational; highlighting the major challenges faced by elected women representatives.

परिचय
73 व 74 वे संविधान संशोधनों के माध्यम से एक तिहाई (1/3) महिला प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। बाद में महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, राजस्थान ने 50% आरक्षण की व्यवस्था की।

उसके महिलाओं में जागरूकता बढ़ी - नेतृत्व क्षमता विकसित हुई। महिला सशक्तिकरण के उपास तेज हुए। जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद् से लेकर राष्ट्रपति के रूप में चुने गये हैं। हालांकि उनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं।

चुनाव का कई जगहें - चुनाव के बाद भी महिलाएं पीछे रहती हैं।

② घुंघर उथा - चुन लिए जाने के बाद भी सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है।

③ सुरक्षा का मामला - कई दुबंगों, अपराधियों द्वारा धमकाना।

④ निर्वाचक वर्ग पहलों में कवटेलना - महत्वपूर्ण निर्णयों में अब भी पुरुषवर्गीय शक्ति।

⑤ उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर कम - MLAs / MPs हेतु निष्पक्षता तक व्यवस्था नहीं। हालांकि नारी वॉन कार्य योजना।

उपरोक्त चुनौतियों के समाधान करें इसलिए हैं जो महिला सशक्तिकरण के उपास हैं - इसके राज्यावत, राष्ट्रीय, जावलीवर्षी, महिला आयोग।

संबंधित रिपोर्ट उदाहरण उदाहरण के उपास से संबंधित।

(Write above this line only)

3. संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना कीजिये।
 Criticize the constitutional amendment process.

संविधान के भाग-20, अनुच्छेद-368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन है।

संशोधन के 3 तरीके \Rightarrow $\frac{1}{2}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{साधारण बहुमत} \\ \text{विशेष बहुमत} \\ \text{विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों का संमर्षन।} \end{array} \right.$

आलोचना के प्रमुख बिंदु

- 1) राज्यों की सहमति नहीं \rightarrow संशोधन हेतु विधानमंडली से परामर्श नहीं लिया जाना, संघात्मक व्यवस्था के अस्तित्व से
- 2) राज्यसभा की कम दायित्व \rightarrow कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्यसभा की दायित्व कम होती है
- 3) संयुक्त अधिवेशन नहीं \rightarrow साधारण कानून हेतु के विपरीत इस हेतु संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं
- 4) राष्ट्रपति पुनः नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर हेतु बाध्य है।
- 5) बहुमत दल की तानाशाही के शोषण की लड़ाई जाते हैं कि कुछ राज्यों में सरकारें के चलते संघीय संरचना में बाधा पड़ते हैं
- 6) छोटे दलों की आवाज \rightarrow आमः अश्रीय दल में आवाज
- 7) 42 भाग का संशोधन \rightarrow 24th संशोधन के फलस्वरूप यह शक्ति / शक्ति को न्यायालय में अल संरचना को बनाए रखते हुए संशोधन की मान्य बतमा

व्यक्तिगत
 कर्म
 दूर
 अन्य
 शो
 के
 साथ
 वलगा
 संघ
 प्रदान
 से

(Write above this line only)

4. राजनीतिक आन्दोलन एवं राजनीतिक दलों में संबंध बताते हुए राजस्थान में दलीय प्रणाली का व्यावहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट करें-

Explain the practical view of the party system in Rajasthan by explaining the relationship between political movements and political parties.

स्वातंत्र्योत्तर राजस्थान में राजनीतिक आंदोलनों के परिचय - इनमें भागीदारी के संबंध में राजनीतिक दलों की

- स्थिति — कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी भी)
- स्वतंत्र पार्टी (पूर्व रिआसतों के नेतृत्व में)
 - रामराज्य पार्टी (लिबरल लोगों द्वारा)

समय की व्यावहारिक दृष्टिकोण गतिशीलता के साथ इनमें व्यापक बदलाव आया। 1960 में राष्ट्रीय ध्वजाक्रम, राष्ट्रपति शासन के बाद जनता दल का उदभव।

वर्तमान में स्थिति	राष्ट्रीय दल	कांग्रेस (69 सीटें)
		भाजपा (115 सीटें)
		बसपा (02 सीटें)
	क्षेत्रीय दल	माजपा (01 सीटें)
		BTP - 3 सीटें
		RLP - 1 सीटें
	निर्दलीय	15 सीटें

वस्तुतः राजस्थान में वर्तमान में द्विदलीय प्रणाली विद्यमान है। इस संबंध में उदारवादी-शरणा व कांग्रेस भाजपा विकासशील - राष्ट्रवादी सोच इच्छित होती है।

1992 के बाद से निरंतर द्विदलीय संस्कार कार्यक्रम में शासन पर स्थापित होती है -

1952
8
2023
25
सीटें-2
सीटें
पर
प्रकार
सीटें

5. पंचायतीराज संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण का उल्लेख करें-
Mention the state's control over Panchayati Raj institutions-

~~परिचय -~~
73^{वें} संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्य, भाकलन, प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तों का अधिकांश राज्य को फिर जिहाई हो।

~~जैसे - पिछले वर्ष की शरभण~~
~~संविधान नियंत्रण~~
- कार्य शापेन (राजस्थान में 29 में से 23 कार्य शापेरित)

~~उत्पादक नियंत्रण~~
- वजरीम शापेन (75:20:5) का इसमें हिस्सा शापेन राज्य वित्त शापेग की धनुशांसापे पर।

~~आभाषिक वित्तीय नियंत्रण~~
शंके शापे संबंधी वित्तावली राज्य सरकार द्वारा तय की जावी है।

→ ग्राम पंचायत के शापेक पंचायतसमिषि व ~~किला शापेक~~ के कुषिमा/प्रमुख का पुनः शिद विसि से होगा मह राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

~~निष्पत्ति~~
→ PESA लागू होने के संबंध में।

व्यापकता उदाहरण

6. भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के विविध रूप/प्रवृत्ति बताते हुए क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या करें-

Briefly explain the ill effects of regionalism by describing the various forms/tendencies of regionalism in Indian politics.

परिचय -
राजनीति में क्षेत्रीयता अपने क्षेत्र के हितों को तवज्जो देना, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना तथा राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों को साधना भूमि-पुत्र की व्यवस्था के आधार पर इन्हें कल मिलता है।
 क्षेत्रीयता के रूप में दालगांववाद की राजनीति
 ⇒ अलग राज्यों के साथ स्वायत्तता की मांग
 ⇒ क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व। ⇒ इग्रवाद
 ⇒ राष्ट्रीय मुद्दों को नगण्य। ⇒ आतंकवाद

उपपिठाव - राष्ट्रीय एकता का कटौत के विरुद्ध
 ⇒ - दालगांववाद की भावना।
 ⇒ - अलग राज्यों की मांग। [गोरखालेख, खलिस्तान]
 ⇒ - हिंसा से विकास अवरुद्ध होता है।
 ⇒ - राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ही जाते हैं।
 ⇒ - राजनीतिक अस्थिरता जैसे खतरों।

विलय क्षेत्रीय उपपिठावों से निपटने हेतु शान्तिपूर्ण तरीके, सहयोगी संघर्ष प्रमुख उपकरण हैं।

(Write above this line only)

7. गिरती हुई संसदीय उत्पादकता एक गंभीर समस्या है। संसदीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिए-
Falling parliamentary productivity is a serious problem. Give your suggestions to increase parliamentary productivity.

संसदीय उत्पादकता संसदीय गतिविधियों यथा-
सत्रों का आयोजन, मिडिंग्स लेना,
उचित निर्णय लेना। सत्रों की कार्यवाही बाधित करने से
संसदीय उत्पादकता है।

4

वर्तमान विपक्षी गतिशीलता व अन्य कारकों की
वजह से वार-वार सत्र आयोजन, विधान,
संसदीय नियमों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या है।

कक्षा
की
वर्षा
3
माघ
उत्तर
करे

- सुझाव → संसदीय साक्षरता बढ़ाना।
- उत्तर → उत्पादकता गिराने वाले कारकों पर एथिक्स
कमेटी निर्णय करे ex. मधुकर मोझा।
- वार-वार उल्लंघन करने पर सदस्यता रद्द हो।
- अनावश्यक सुझावों पर नियंत्रण न हो।
- आपकी व राजनीतिक गतिशीलता के संबंध में
संसदीय कार्यवाही व्यवस्था करें।
- संबंधित राजनीतिक इलाही जवाबदेयता सुनिश्चित
हो।

इस प्रकार संसदीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संसदीय गतिशीलता को नियंत्रित करना आवश्यक है।
संसदीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संसदीय गतिशीलता को नियंत्रित करना आवश्यक है।

1. मुहावरे

अंक - 5

(i) अपना किया पाना

(ii) न इधर का होना न उधर का

(iii) एहसान फरामोश होना

(iv) चींटी के पर निकलना

(v) चक्की में जुटे रहना

2. विलोम शब्द

अंक - 5

(i) अघ -

(ii) अनुरूप -

(iii) कर्ता -

(iv) क्षम -

(v) गत -

(vi) चर -

(vii) दिव्य -

(viii) पर -

(ix) मुख -

(x) विलास -

(A) Choose the correct word/phrase and rewrite the correct form of the following sentences: (Q. No. 1-10)

Marks 10

1. He went there so that he can/might borrow money.

2. She advised that I should/should have curtail expenditure.

3. She shall/must not have left alone as it was raining heavily.

4. You ought to/should have stood by your sister, when she was in difficulties.

5. My friend did not help me though he should/could have helped.

6. He is to have/is to catch the first train tonight.

7. He would/should go to college daily by bus in his college days.

8. You need not to/need not bring your notebooks from tomorrow.

(B) Supply correct tense form of the verbs given in brackets: (Q. No. 9)

Marks 6

9. The city of Katagum _____ (build) in the form of an oblong with the chief's house in the centre _____ (look) like an old English castle. There _____ (be) a high clay tower, with a wall around it about twenty feet high; inside the courtyard _____ (be) small houses for women and servants.

(C) Change the following sentences from Active form to Passive form: (Q. No. 10-15) Marks 6

10. War will destroy everything.

11. The government is spending too much money on Operation blue.

12. The judge advised me to settle the matter out of court.

13. They rejected his proposal and laughed at him.

14. Social work interests Mr. Kumar very much.

15. It is time to stop writing.